2 अलग-अलग जगहों पर हुई चाकूबाजी की वारदात में लंदन में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य को घायल अवस्था में पाया गया। पहली घटना वाल्थमस्टो के ब्रोमले रोड की है। वहीं दूसरी घटना में लंदन के बार्नेट इलाके में घटित हुई।

बदल रही सऊदी अरब की तस्वीर

महिलाओं पर सख्त प्रतिबंधों और तंगदिली के लिए बदनाम रहा सऊदी अरब अब तेजी से बदलाव की राह पर जाता दिखाई दे रहा है। महिलाओं को हाल के दिनों में ड्राइविंग की अनुमति देकर रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियां तोड़ चुका है। अब राजधानी रियाद के बाहरी इलाके बनबन में इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक महोत्सव की इजाजत देकर एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इस महोत्सव में सऊदी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर शिरकत की और संगीत का भरपूर आनंद उठाया। इस उदारवादी नजरिए के लिए क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान को श्रेय दिया जा रहा है। एएफपी

साइंस फाउंडेशन के नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतवंशी को चुना

- एनएसएफ के अगले निदेशक होंगे सेतुरमन पंचनाथन
- आइआइटी मद्रास और आइआइएस-बेंगलुरु से पढ़ाई कर चुके हैं पंचनाथन
- विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देती है एनएसएफ

भारतवंशी कंप्यूटर वैज्ञानिक सेतुरमन पंचनाथन की फाइल फोटो। साभार : एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी वैज्ञानिक सेतुरमन पंचनाथन (58) को प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) का अगला निदेशक चुना है। पंचनाथन फ्रांस के कोर्डोवा की जगह लेंगे। एनएसएफ निदेशक के तौर पर कोर्डोवा का छह साल का कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है। बता दें कि एनएसएफ एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है, जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसी तरह का ही एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआइए) है।

व्हाइट हाउस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के निदेशक केल्विन ड्रोगेमीयर ने बताया, 'कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉ. पंचनाथन का शोध-अनुसंधान के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। इसी को ध्यान में रखकर उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।' अपनी नियुक्ति पर पंचनाथन ने कहा कि वह सम्मनित महसूस कर रहे हैं। पंचनाथन ने 1981 में मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक के बाद 1984 में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएस) से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1986 में उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री लेने के साथ ही 1989 में कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की। पंचनाथन वर्तमान में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (एएसयू) में एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुख्य अनुसंधान और नवाचार अधिकारी हैं। वह इसी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कॉग्निटिव यूबिकिटस कंप्यूटिंग के संस्थापक निदेशक भी हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सीनेट अविलंब महाभियोग चलाए

- डेमोक्रेट पर बगैर सुबूत, बिना सफाई मांगे फैसला करने का आरोप

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के उच्च सदन सीनेट से खुद पर अविलंब महाभियोग चलाने की मांग की है। कहा है कि प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट सांसदों ने बचाव के लिए उन्हें न तो वकील दिया, न कोई गवाह पेश किया, कुछ नहीं किया। इसलिए अब वह सीनेट से पूछ रहे हैं कि वे कैसे महाभियोग चलाएंगे। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन समेत सात संभावित उम्मीदवारों ने एक साथ ट्रंप पर हमला बोला है, लेकिन वे आपस में ही उलझते नजर आए।

बुधवार को प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ दो आरोप- सत्ता के दुरुपयोग और संसदीय जांच को बाधित करने के आरोप तय हुए थे। इसके बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले सदन ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। अब यह प्रस्ताव सीनेट में जाएगा, जहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। यहां कुल 100 सीटों में 53 पर रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा है। वरिष्ठ सीनेटर मिच मैककॉनेल के महाभियोग को लेकर आए बयान के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां पर सही प्रक्रिया न अपनाए जाने की आशंका जताई है। माना जा रहा है कि सीनेट में महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव जनवरी में पेश होगा। ट्रंप ने ट्वीट में कहा, मामले में कोई सुबूत नहीं है। वे (डेमोक्रेट) उसे दिखा नहीं पाए। वे मुझे हटाना चाहते हैं। मैं भी मामले की जल्दी सुनवाई चाहता हूं। अमेरिका के इतिहास में एंड्यू जॉनसन और बिल क्लिंटन के बाद ट्रंप ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग चल रहा है। अमेरिका के संविधान के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन महाभियोग को लेकर खुद भी अपनी पूरी प्रक्रिया चला सकता है। लेकिन राष्ट्रपति तभी सत्ताच्युत होंगे जब सीनेट के दो तिहाई सदस्य (67) महाभियोग के पक्ष में मतदान करेंगे।

तुलसी गबार्ड की हो रही आलोचना : उधर, भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड की बुधवार को प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ आए महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग से अनुपस्थित रहने के कारण आलोचना हो रही है। गबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हवाई से सांसद हैं।

न्यूज गैलरी

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी (बाएं) और जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो। एपी

ईरानी राष्ट्रपति ने जापान के पीएम से मुलाकात की

टोक्यो : अमेरिका से जारी तनातनी के बीच ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी शुक्रवार को जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो से मिलने टोक्यो पहुंचे। किसी ईरानी राष्ट्रपति का बीते दो दशक में जापान का यह पहला दौरा है। टोक्यो पहुंचने पर रूहानी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अपने परमाणु कार्यक्रम के चलते आर्थिक पाबंदियों का सामना कर रहे ईरान और अमेरिका के बीच जापान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। (एएफपी)

पाकिस्तान में पोलियो के 111 मामले सामने आए

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में इस साल पोलियो संक्रमण के कुल 111 मामले सामने आ चुके हैं। देश के पोलियो उन्मूलन विभाग ने जानकारी दी कि बीते बुधवार को अलग-अलग प्रांतों से संक्रमण के सात नए मामले प्रकाश में आए हैं। अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ-साथ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पोलियो का प्रकोप अभी भी जारी है। पाकिस्तान में 2012 से लेकर अब तक पोलियो उन्मूलन अभियान से जुटे 68 लोगों की हत्या हो चुकी है। (प्रेट्र)

हंबनटोटा पोर्ट की सुरक्षा अपने हाथ में रखेगा श्रीलंका

कोलंबो : श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कहा है कि चीन द्वारा निर्मित हंबनटोटा पोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा उनका देश अपने हाथ में ही रखेगा। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए राजपक्षे ने कहा कि बंदरगाह के वाणिज्यिक पहलू को लेकर चीन के साथ 99 साल के करार को तो वे नहीं बदलने जा रहे, लेकिन इसकी सुरक्षा का सारा दायित्व श्रीलंका खुद संभालेगा। श्रीलंका इस मुद्दे पर चीन के साथ बातचीत करने को तैयार है। (आइएएनएस)

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से तीन की मौत

सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग से तीन लोगों की मौत की खबर है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मरने वालों में दो स्वयंसेवी शामिल हैं। घटना साउथ ऑस्ट्रेलिया प्रांत की है। आग की चपेट में आने से करीब एक दर्जन लोगों के घायल होने की भी सूचना है। देश के जंगली इलाकों में पिछले महीने से आग की विभीषिका जारी है। (आइएएनएस)

मानवाधिकार मामला ▶ यूरोपीय संघ की संसद ने बीजिंग पर बोला जोरदार हमला

उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर चीनी अफसरों पर लगाया जाए प्रतिबंध

कहा- चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड में नहीं हुई है कोई उल्लेखनीय प्रगति

स्ट्रासबर्ग, एएफपी: यूरोपीय संघ की संसद ने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ किए जा रहे बर्ताव पर बीजिंग पर जोरदार हमला बोला है। संसद ने इसके लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने का आह्वान किया है। संसद के सदस्यों ने गुरुवार को स्वीकार किए गए एक संकल्प पत्र में कहा कि यूरोपीय यूनियन द्वारा अब तक अपनाए गए तरीकों से चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में इस तरह के प्रतिबंधों को लगाए जाने पर विचार करना चाहिए।

यूरोपीय संघ की संसद ने एक बयान में कहा, 'यूरोपीय संसद के सदस्य अपील करते हैं कि अगर उचित और प्रभावी माना जाए तो शिनजियांग प्रांत में बुनियादी अधिकारों के गंभीर दमन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाए और उनकी संपत्ति फ्रीज की जाए।' बयान में आगे कहा गया है कि संसद चीन की सरकार से आग्रह करती है कि वह बिना किसी आरोप, मुकदमे या दोषसिद्धि के मनमाने ढंग से हिरासत में रखने की प्रथा को तुरंत खत्म करे और इल्हाम तोहती समेत हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करे। बता दें कि तोहती को इस साल के सखारोव पुरस्कार से नवाजा गया है।

बुधवार को यूरोपीय संसद ने जेल में बंद उइगर बुद्धिजीवी तोहती की बेटी को यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूरोपीय संघ संसद द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सोवियत भौतिक विज्ञानी आंद्रे सखारोव की स्मृति में प्रदान किया जाता है। दरअसल, चीन ने लगभग 10 लाख उइगर अल्पसंख्यकों (अधिकांश मुस्लिम) को हिरासत शिविरों में बंद कर रखा है जिसके चलते उसे अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

बीजिंग ने शुरुआत में तो ऐसे शिविरों के अस्तित्व से इन्कार किया था, लेकिन अब उसका कहना है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस तरह के जातीय अल्पसंख्यकों को हिरासत शिविर (चीन इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहता है) में रखना आवश्यक है।

हांगकांग और मकाउ पर चीनी राष्ट्रपति ने दुनिया को चेताया

मकाउ, रायटर : चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपने प्रशासनिक क्षेत्रों हांगकांग और मकाउ को लेकर दुनिया को आगाह किया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन (इयू) का नाम लिए बगैर खरी-खरी सुनाते हुए चिनफिंग ने कहा कि चीन अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में विदेशी ताकतों को दखल की कभी इजाजत नहीं देगा। चीनी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया, जब हाल ही में अमेरिका ने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया है। ब्रिटेन और ईयू भी हांगकांग पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं।

राष्ट्रपति चिनफिंग ने यह सख्त संदेश शुक्रवार को यहां चीन को मकाउ सौंपे जाने की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में दिया। इस मौके पर मकाउ में चीन समर्थित नई सरकार को शपथ भी दिलाई गई। मकाउ के नए मुख्य कार्यकारी के तौर पर हो लाट सेंग (44) ने शपथ ली। चीन के इस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए सेंग का चयन गत अगस्त में किया गया था। चिनफिंग ने कहा, 'मुझे हांगकांग और मकाउ के चीन में वापसी को महत्व देना चाहिए। इन दोनों विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों का मसला पूरी तरह चीन का आतंरिक मामला है। इसमें विदेशी ताकतों का कोई काम नहीं है। हम किसी भी बाहरी ताकत को दखल की इजाजत नहीं देंगे।'

1999 में चीन को सौंपा गया था मकाउ

20 दिसंबर, 1999 को मकाउ चीनी शासन के दायरे में आया था। इससे पहले इस क्षेत्र पर पुर्तगाल का शासन था। जबकि 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग इस शर्त के साथ को चीन सौंपा था कि वह इस क्षेत्र की स्वायत्तता को बनाए रखेगा। हांगकांग जून से विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है।

उत्तर दिशा से हुआ था सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला

सऊदी अरब की तेल कंपनी अरैमको में हमले से क्षतिग्रस्त हुआ शेड। फाइल/रायटर

वाशिंगटन, रायटर: अमेरिका ने कहा है कि 14 सितंबर को सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला उत्तर दिशा की तरफ से किया गया था। हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मलबे के विश्लेषण से इसके संकेत मिलते हैं। यह नई जांच अमेरिका की उस बात की पुष्टि करती है, जिसमें उसने हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया था।

अपनी जांच संबंधी अंतरिम रिपोर्ट में वाशिंगटन ने कहा है कि निर्धारित लक्ष्यों को निशाना बनाने से पहले ड्रोन उत्तर-पश्चिम में लगभग 200 किमी (124 मील) दूर एक स्थान तक गया था। मानवरहित यान (यूएवी) के अधिकतम 900 किलोमीटर की दूरी तय करने से पता चलता है कि हमला सरकारी तेल कंपनी अरामको के अब्कैक स्थित सबसे बड़े तेल शोधन संयंत्र के उत्तर से किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में तेल ठिकाने पर किए गए ड्रोन हमले और ईरान द्वारा निर्मित मानवरहित विमान आइआरएन-05 यूएवी में बहुत सी समानताएं मिली हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हथियारों के मलबे के विश्लेषण से यह नहीं कहा जा सकता है कि आखिर हमला किस निश्चित जगह से किया गया। बता दें कि 14 सितंबर को सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हुए हमलों के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि हूती विद्रोहियों का समर्थन करने वाले ईरान ने हमलों में अपनी किसी भूमिका से इन्कार किया था।

पाक के प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हो रहा है दुष्प्रचार

- मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाने के बाद आलोचना से आहत हैं सेवानिवृत्त होने जा रहे आसिफ सईद खोसा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वह अपनी स्वच्छ अंतरात्मा के साथ सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देशद्रोह के मामले में पूर्व सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाने के बाद उनके और न्यायपालिका के खिलाफ दुष्प्रचार छेड़ दिया गया है।

शुक्रवार मध्य रात्रि को सेवानिवृत्त होने जा रहे 64 वर्षीय खोसा ने कहा कि न्यायपालिका और उन्हें आलोचना में घसीटा जा रहा है। विशेष कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को छह साल पुराने देशद्रोह के मामले में मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई थी। उन्हें 2007 में संविधान को निष्प्रभावी बनाने के लिए यह सजा सुनाई गई है।

इस सजा के बाद देश की ताकतवर सेना और इमरान खान सरकार न्यायपालिका से नाराज हो गई है। कानून मंत्री फारोह नसीम ने गुरुवार को कहा कि जिस न्यायाधीश ने फैसला लिखा वह मानसिक रूप से बीमार है और उसे काम करने से रोका जाना चाहिए।

ब्रिटेन में शिक्षित खोसा ने कहा, 'न्यायपालिका और मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हुआ है। आरोप निराधार और गलत हैं। हम अपनी शक्ति की सीमाएं जानते हैं और यह भी जानते हैं कि सच हमेशा कायम रहता है।'

अपने सम्मान में जुटे कोर्ट के कर्मचारियों से निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'मैंने 100 फीसद काम करने का प्रयास किया, अपने कर्तव्य से परे जाकर करने का प्रयास किया, कभी कुछ बोला नहीं, जो भी कहा अपनी कलम के माध्यम से कहा, कभी अकारण फैसला नहीं रोका और इस सार्वजनिक सेवा को अपने जीवन के बेहतरीन साल देने के बाद आज मैं अपना यह परिधान अपनी उस अंतरात्मा के साथ उतारने जा रहा हूं जो एकदम साफ है।'

दुष्कर्म के खिलाफ आवाज

दुष्कर्म और महिला हिंसा को लेकर भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में आवाजें उठने लगी हैं। यह तस्वीर दक्षिण अमेरिकी देश चिली के सैंटियागो की है, जहां फैमिनिस्ट समूह 'लास्टीसिस' के विशेष अभियान 'ए रेपिस्ट इन योअर वे' के अंतर्गत हजारों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ए रेपिस्ट इन योअर वे एक गीत है, जो इन दिनों दुष्कर्म व महिला हिंसा के विरोध के लिए प्रतीक बन गया है। यह गीत सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। एएफपी

दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं शरीफ

लंदन, आइएएनएस : ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिल की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। एक मेडिकल जांच में यह पता चला है। शरीफ के निजी चिकित्सक डॉ. अदनान खान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया, लंदन स्थित हेयरफिल्ड हॉस्पिटल में हुई मेडिकल जांच में नवाज शरीफ की हृदय संबंधी गंभीर बीमारी का पता चला है। इसे लेकर अगले स्तर की जांच भी होनी है। बीमार पूर्व पीएम रक्त में प्लेटलेट्स की कमी की समस्या से पहले ही जूझ रहे हैं।

नवाज शरीफ। फाइल

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता शरीफ को इलाज के लिए बीते 19 नवंबर को लंदन लाया गया था। भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद शरीफ की हालत ज्यादा खराब होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलाज के लिए उन्हें जमानत मिली थी।

कार्रवाई

फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने उठाया कदम, गूगल एड्स पेज पर अस्पष्ट विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप

गूगल पर लगाया 1184 करोड़ का जुर्माना

- इससे पहले कंपनी एक दूसरे मामले में करीब एक अरब रुपये जुर्माना देने को हुई थी तैयार

पेरिस, रायटर : फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने गूगल एड्स पेज पर अस्पष्ट विज्ञापनों के प्रसारण और प्रतियोगिता के प्रतिकूल आचरण के मामले में सर्च इंजन पर 150 मिलियन डॉलर (करीब 1184.78 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। गूगल ने इस मामले में अपील दाखिल करने की बात कही है।

फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश गूगल, फेसबुक, एपल और अमेजन आदि अमेरिकी तकनीकी कंपनियों की उच्चस्तरीय जांच करते हैं। इसी साल सितंबर में गूगल चार साल से चल रहे राजकोषीय धोखाधड़ी के मामले को खत्म करने के लिए फ्रांस के प्राधिकार को करीब एक अरब रुपये देने को तैयार हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल खोज परिणामों के साथ व गूगल एड्स (ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म) पर प्रवर्तकों के विज्ञापन दिखाए जाने के मामले में सख्त जांच का सामना कर रहा है। फ्रांस प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के प्रमुख इसाबेल डी सिल्वा ने प्रेस वार्ता में कहा कि ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार के मामले में गूगल बाजार में 90 फीसद की हिस्सेदारी रखता है।

प्रतीकात्मक

इसी साल जनवरी में फ्रांसिसी डाटा सुरक्षा के निगरानीकर्ता ने यूरोपीय यूनियन की गोपनीयता नीति के उल्लंघन के मामले में गूगल पर 50 मिलियन यूरो (करीब 395 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था। उसने कहा था कि गूगल ने गोपनीयता भंग की और विज्ञापनों के मामले में जरूरत के बावजूद संबंधित से सहमति नहीं ली।

अमेरिका में जनगणना के दौरान अफवाहों पर प्रतिबंध लगाएगा फेसबुक

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : अमेरिका में अगले साल पहली बार होने वाली ऑनलाइन जनगणना को लेकर फेसबुक ने अपनी नीति तैयार की है। उसने जनगणना के दौरान अफवाहों को रोकने तथा नई विज्ञापन नीति अमल में लाने का फैसला किया है। इस दौरान वह ऐसा कोई विज्ञापन नहीं चलाएगा, जिसमें जनगणना का विरोध किया गया हो या उसमें न शामिल होने की अपील की गई हो। फेसबुक की अमेरिकी नीति के उपाध्यक्ष केविन मार्टिन व उत्पाद प्रबंधन निदेशक एस. चक्रवर्ती ने कहा, 'हमें फेसबुक पर जनगणना संबंधी पोस्ट व विज्ञापन को लेकर सतर्क होना होगा। हम देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गणना का समर्थन करते हैं।'

सीरिया में हुई बमबारी तुर्की सीमा की तरफ भागे हजारों लोग

बेरुत, रायटर : रूसी सैन्य बल और सीरियाई सेना की तरफ से की गई भीषण बमबारी के बाद विद्रोहियों के दबदबे वाले उत्तर-पश्चिम सीरिया से हजारों की संख्या में लोग तुर्की सीमा की तरफ पलायन के लिए मजबूर हो गए। स्थानीय लोगों व राहत दल के सदस्यों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मारात अल नुमान से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया। इसके कारण वहां वाहनों की लंबी कतार देखी गई। मारात अल नुमान विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। वहां रूसी और तुर्की सेना अकसर एयर स्ट्राइक समेत अन्य हमले करती रहती है।

बचाव दल ने बताया कि पिछली रात एयर स्ट्राइक में इलाके के एक गांव के 11 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार, आवासीय इलाकों में हुए हमलों में इस साल अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं।

26.7 करोड़ फेसबुक यूजर का डाटा ऑनलाइन लीक : रिपोर्ट

- ज्यादातर अमेरिकी यूजर हुए प्रभावित, लीक जानकारियों में यूजर आइडी, फोन नंबर व पूरा नाम शामिल

लंदन, आइएएनएस : फेसबुक यूजर के डाटा लीक का एक और बड़ा मामला सामने आया है। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली ब्रिटेन की कंपनियों ने गुरुवार को दावा किया कि 26.7 करोड़ फेसबुक यूजर का डाटा वेब पर सार्वजनिक हो चुका है। इनमें फेसबुक यूजर की आइडी, फोन नवंबर और पूरा नाम शामिल है। डाटा लीक से प्रभावित ज्यादातर यूजर अमेरिकी हैं।

तकनीकी शोध करने वाली ब्रिटिश कंपनी कंपेरिटेक और सुरक्षा मामलों में शोध करने वाली बॉब डियाचेंको का मानना है कि वियतनाम के साइबर अपराधी इन डाटा का इस्तेमाल करते हुए अवैध स्क्रैपिंग या फेसबुक एपीआइ के दुरुपयोग जैसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तेजी के साथ किसी भी वेब पेज पर उपलब्ध डाटा को कॉपी करने के काम को स्क्रैपिंग कहा जाता है। यही नहीं, डाटा बेस पर उपलब्ध सूचनाओं के जरिये यूजर को एसएमएस फर्जीवाड़ा या फर्जी योजनाओं का शिकार बनाया जा सकता है।

डाटा लीक का नया मामला उस समय प्रकाश में आया है जब कैंब्रिज अनालिटिका घोटाले के कारण खो चुके विश्वास को फेसबुक दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। 26.7 करोड़ फेसबुक यूजर का डाटा सार्वजनिक होने के मामले का पता लगाने के बाद डियाचेंको ने आइपी एड्रेस का प्रबंधन करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाता को सूचित किया, ताकि इन्हें वेब से हटाया जा सके। हालांकि, यह डाटा डाउनलोड के तौर पर एक हैकर फोरम पर पोस्ट किया जा चुका है।

यह पहला मौका नहीं है जब इस प्रकार का डाटा सार्वजनिक हुआ है। इसी साल सितंबर में 41.9 करोड़ डाटा लीक हुए थे, जिनमें फेसबुक यूजर की आइडी और फोन नंबर शामिल थे।